the surrounding rural scene without detriment to their main task. These guidelines are broadly in line with the thinking of the present Government.

(b) Details of development work undertaken by the Bokaro Steel Plant in the neighbouring villages during 1979 are given below:—

	Amount Spent Rs.
1. *Adult Education*	
No. of adult covered—1129	14,800
2. *Medical*	
No. of patients covered—1170 (Medicined distributed)	1,170
3. *Veterinary*	
(No. of animals treated-331 (Medicines given)	250
4. *Public Health*	
Disinfection of M7 wells and 4 ponds proper-anti-mosquitoes and anti-larves measures undertaken.	Separtate account not kept
5. *Walkway Bridge*	
Accross river Ganga (1651' long and 4/ wide) constructed for the benefit of villagers to come to the Steel township	1,00,000

During the current year (January-March, 1980) Adult Education, Medical, Veterinary and Public Health measures are being continued. In addition, sinking of 20 hand-pumps at a cost of Rs. 35,035 is in progress. Further, steps have also been taken for repairing and roofing of five school buildings at an estimated cost of about Rs. 1.25 lakhs in the villages of Kandra, Kantidi, Satanpur, Amdihia and Sibbandih, and for repairing the road leading to Chas Cremation Ground at a cost of about Rs. 63,000/-.

खाद्य तेलों की अनुमानित कमी

2174. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979–80 के दौरान कुल मांग की तुलना में खाद्य तेलों की अनुमानित कमी कितनी है;

(ख) अनुमानित उत्पादन और मांग की अलग-अलग मात्रा क्या है;

(ग) इस वर्ष के प्रारम्भ में राज्य व्यापार निगम के पास इसका कितना स्टाक था?

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिये कितनी मात्रा में तेल का आयात किया जा रहा है और इस दिशा में किये जा रहे अन्य उपाय क्या है;

(ङ) बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये आयातित तेल का उपयोग करने का प्रस्तावित तरीका क्या है; और

(च) क्या तेल का आयात करने के लिये प्राइवेट पार्टियों को अनुमति दी जा रही है अथवा अनुमति देने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). खाद्य तेलों के लिये योजना पहली नवम्बर से आरम्भ होने वाले तेल वर्ष के आधार पर बनाई जाती है।

तेल वर्ष 1979–80 के दौरान खाद्य तेलों की मांग तथा देश में उनकी उपलब्धता में इस समय लगभग 10 लाख मीटरी टन का अंतर होने का अनुमान है। खाद्य तेलों का उत्पादन लगभग 27 लाख मी० टन तथा मांग के लगभग 37 लाख मी० टन होने का अनुमान है;

(ग) पहली नवम्बर, 1979 को जब चालू तेल वर्ष आरम्भ हुआ, लगभग 2.19 लाख मीटरी टन।

(घ) मांग तथा देश में खाद्य तेलों की उपलभ्यता के बीच के अन्तर को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिये खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा का आयात जारी रखने का प्रस्ताव है, ताकि विभिन्न उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तेल वर्ष 1979-80 के दौरान आयात की ठीक-ठीक मात्रा इन बातों पर निर्भर करेगी—देश में तेलों का उत्पादन स्तर, देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य रुख, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य संगत बातें। इसके अलावा, देश मे खाद्य तिलहनों और तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कदम भी उठाये गये है;

(ङ) राज्य व्यापार निगम वनस्पति उद्योग जैसे उपभोक्ताओं को आयातित तेल उपलब्ध करता रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को लाइसेंसशुदा उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिये आयातित तेल अधिक मात्रा मे दिये जा रहे है। राज्य व्यापार निगम समय-समय पर कुछ चुने केन्द्रों में आवश्यकतानुसार बाजार दखल के उपाय के रूप में खाद्य तेलों की वाणिज्यिक बिक्री भी करता रहा है, ताकि मूल्यों के बढ़ते रुख को रोका जा सके।

(च) जी नहीं। नीति के तौर पर खाद्य तेलों का आयात 2 दिसम्बर, 1978 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है। तथापि, प्राइवेट पार्टियों को कुछ लाइसेंस दिये गये हैं; ये लाइसेंस कुछ उच्च न्यायालयों के आदेशों के कार्यान्वयन के रूप में और उन प्राइवेट पार्टियों द्वारा दायर की गई अपीलों पर दिये गये अंतिम आदेशों के परिणामस्वरूप दिये गये जिनके लाइसेंस के आवेदन मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात द्वारा अस्वीकार कर दिये गये थे।

चाय बागानों द्वारा चाय की बिक्री

2175. **श्री कृष्णा कुमार गोयल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय बागानों द्वारा चाय की बिक्री के लिये अपनाई जा रही प्रक्रिया से संतुष्ट है;

(ख) क्या इस मामले की जांच करने के लिये कोई समिति गठित की गई थी, यदि हां, तो उस समिति का नाम क्या है और उसका प्रतिवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) समिति के प्रतिवेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) चाय बागानों द्वारा बिक्री के वर्तमान तरीके, जिनमे भारत या लन्दन में मुख्य रूप से नीलामी करके बिक्री करने और विदेशी खरीदारों या घरेलू खरीदारों को सीधे बिक्री करने के तरीके शामिल है, एक शताब्दी से भी अधिक समय से चल रहे है और कुल मिलाकर समय की कसौटी पर खरे उतरे है। तथापि, अन्य चाय निर्यातक देशों के साथ प्रतियोगिता बढ़ जाने, आन्तरिक खपत बढ़ जाने और विश्व चाय उद्योग तथा व्यापार के ढांचे में अन्य परिवर्तनों के आ जाने से सरकार ने इस प्रणाली की समीक्षा करना वांछनीय समझा ताकि ऐसे उपचारात्मक उपाय किये जा सकें जो नये परिवर्तनों को देखते हुए आवश्यक हों।

चाय बागानों द्वारा चाय की बिक्री सहित चाय की विपणन प्रणाली की जांच करने के लिए फरवरी, 1978 में श्री पी० एल० टंडन के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की गई थी।